वस्त्र निर्यात कोटे की काला बाजारी

3843. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा जारी वस्त्र निर्यात कोटे को काले बाजार में बेचा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान दोषी फर्मों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है और उन फर्मों के नाम क्या हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) परिधान निर्यात हकदारी वितरण नीति के अन्तर्गत कार्य निष्पादनोत्तर हकदारी पद्धति और गैर-कोटा निर्यातक हकदारी पद्धति के अन्तर्गत हकदारी पंजीकृत परिधान निर्यातकों के माध्य स्थानान्तरणीय है। चूंकि कुछ श्रेणियों में हकदारी की उपलब्धता मांग से कम हैं, यह संभव है कि इस प्रकार के अन्तरण, अन्तरण करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रीमियम की कुछ राशि देने पर किये जाते हों।

एक सांसद से शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक निर्यातक कोटा के काला बाजारी में लिप्त है। मामला जांचाधीन है।

Winding up of Silk Industry in Assam

3844. SHRI BHADRESWAR GOHAIN: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether the Government is aware that the famous silk industry in Assam is gradually fading away and in due course it may be extinct altogether; and

(b) what steps are being taken by the Government to streamline this age-old cottage industry of Assam?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) No, Sir. The production of raw silk, which was 422 metric tonnes in 1990-91, has increased to 469 metric tonnes in the year 1992-93.

(b) In order to increase raw silk production in the State of Assam, the Central Silk Board (CSB) is implementing a pilot sericulture project in the State under the World Bank /Swiss assisted National Sericulture Project. Further, in order to supplement the efforts of the State Government, the CSB has established a network of its units for extending necessary research, extension, infrastructural and training support for development of sericulture industry in the State.

गुजरात क्षेत्र में हथकरघा विकास के लिए कल्याणकारी योजनाएं

3845. **श्री रामसिंह राठवा :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हथकरघा विकास कार्यक्रम के अधीन गुजरात के आदिवासी बहुल और पिछड़े जिलों के लिए कोई कल्याणकारी योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उक्त कल्याणकारी योजनाओं को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) हथकरघा क्षेत्र में संचालित सभी कल्याणकारी योजनाएं जनजातीय बाहुल्य और पिछड़े जिलों के लिए भी उपलब्ध हैं। इन योजनाओं में कार्यशाला-सह-आवास योजना, समूह बीमा योजना, स्वास्थ्य पैकेज योजना और थ्रिफ्ट फंड योजना शामिल हैं। ये योजनाएं चालू योजनाएं हैं और इन्हें निरंतर आधार पर कार्यान्वित किया जाता है। तथापि इन योजनाओं के